262

प्रेषक.

एम0एच0 खान, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

'निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक- 2 | मार्च, 2013

विषयः—जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्र संख्या 01/नगरीय अनुभाग—जेएनएनयूआरएम/01, दिनांक 02—01—2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज परियोजना हेतु परियोजनान्तर्गत प्राप्त केंद्रांश के सापेक्ष राज्य द्वारा सुधारो (Reforms) का कियान्वयन नहीं किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा कटौती की गयी 10% की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त परियोजना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या— भा०स० 146/IV(2)—श०वि0—09—18(एनयूआरएम)/08, दिनांक 13—7—2009, संख्या भा०स० 168/IV(2)—श०वि0—11—18(एनयूआरएम)/08, दिनांक 29—9—2011, संख्या भा०स० 375/IV(2)—श०वि0—11—18(एनयूआरएम)/08, दिनांक 20—3—2012 व संख्या भा०स० 617/IV(2)—श०वि0—09—18(एनयूआरएम)/08, दिनांक 14—5—2012 के माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज परियोजना हेतु स्वीकृत लागत ₹ 5465.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से तीन किस्तों में प्राप्त केन्द्रांश ₹ 2841.55 लाख व राज्यांश ₹ 819.69 लाख सहित अब तक कुल ₹ 3661.24 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3— उक्त परियोजना हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PF-I/2011-587, दिनांक 01-09-2011 द्वारा अवमुक्त की गयी द्वितीय किस्त में राज्य

द्वारा रिफार्म्स का कियान्वयन नहीं किए जाने के कारण परियोजनान्तर्गत कुल केन्द्रांश के सापेक्ष 10% की धनराशि की कटौती की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा कटौती की गयी 10% की धनराशि के क्रम में कार्यहित में इस समय शासनादेश दिनांक— 20 मार्च 2012, से अवमुक्त ₹ 109.30 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए केन्द्रांश कटौती के सापेक्ष शेष धनराशि में ₹ 327.90 लाख (₹ तीन करोड सत्ताईस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत इंगित सुधारों (Reforms) का क्रियान्वयन यथाशीघ्र पूर्ति करायी जाए तथा कंटौती की गई केन्द्रांश की राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए और साथ ही सुधार लागू न किये जा पाने के कारणों को ज्ञात कर जिम्मेदारी / उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए।

4— उक्त धनराशि ₹ 327.90 लाख (₹ तीन करोड सत्ताईस लाख नब्बे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बंधित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे आहरित करके निगम के पी0एल0ए0 खाते में जमा की जायेगी तथा

पी०एल०ए० से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

5— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13, लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—05—नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन—20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं० 1038/XXVII(2)/2012, दिनांक-14 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमित से जारी किये जा रहे हैं।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28—3—2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलोटमेनट आई डी—\$1303130398 — के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय, (एम०एच० खान) सचिव।

सं0 भा सः 74/IV(2)-श0वि0—12—11(जेएनएनयूआरएम)/10, तद्दिनांक। प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।

6. वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।

7. जिलाधिकारी, देहरादून।

8. बित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

9. निदेशक, एन0आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।

10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से, (सुमाष चन्द्र) उप सचिव।